श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शोक प्रकटीकरण के कोई खिलाफ नही है। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा जो पजाब और हरियाणा मे हो रहा है ?

12.41 hrs.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY-GENERAL : Sir, I lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together today.

President's Address

माननीय सदस्यगण,

मुझे वर्ष 1984 मे ससद् के इस पहले अधिवशन मे आपका स्वागत करते हुए बडी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामन जो बजट और विधान कार्य है उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मै आपको अपनी शुभकामनाए देता हू ।

2. चालू वर्ष मे हमारी अर्थ-व्यवस्था मे भारी सुधार हुआ हे, जिससे व्यापक रूप से वर्षा न होन के कारण हुई हानि को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष कृषि उत्पादन म 9 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जबकि पिछले वर्ष कृषि उत्पादन मे 4 प्रतिशत की कमी हुई थी। अनाज का उत्पादन 1420 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक हो जाने की आशा हे, जबकि 1982-83 मे वास्तविक उत्पादन 1284 लाख मीट्रिक टन था और इससे पहले सबसे अधिक उत्पादन का रिकार्ड 1333 लाख मीट्रिक टन रहा था। कृषि उत्पादन मे ये सफलताए वर्षों से अपनाई गई हमारी ठास नीतियो और कार्यक्रमो का ही परिणाम है। 1982-83 म सिचाई क्षमता म 23.4 लाख हेक्टेयर की बढ़ातरी हुई थी। अब 1983-84 मे इसम 23.7 लाख हेक्टयर की वृद्धि होने की सम्भावना है। सिचाई मे जो क्षमता हासिल की गई है उसके उपयोग म सुधार लाने के लिए खासतार से कोशिशे की जा रही हे। अधिक पैदावार देने वाली फसलों की किस्मो के कार्यक्रमों मे विस्तार किया जाता रहा है और यह उम्मीद है कि 1983-84 में 520 लाख हेक्टेयर भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगी। 1983-84 के दौरान उर्वरक की खपत योजना लक्ष्य से काफी अधिक हो जाएगी।

3. सूखी भूमि पर खेती की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है और नई टेक्नॉलोजी को अपनाने के लिए 4246 लघु-जल विभाजको का पता लगाया गया है। इससे गरीब से गरीब ग्रामीण समुदायो को सहायता मिलेगी। 1983-84 मे छोटे और सीमान्त किसानो की सहायता के लिए केन्द्रीय रूप मे चलाई गई एक योजना शुरू की गई थी।

4. औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था को फिर से ठीक करने और बुनियादी ढाचे मे सुधार का काम पूरी गति से चलता रहा। कोयले के उत्पादन मे सितम्बर के बाद लगातार सुधार हुआ है और 1983-84 के दौरान इसका उत्पादन 1400 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुच जाएगा। 1983-84 के पहले 9 महीनो के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग 5 प्रतिशत बढ़ गया है। खनिज तेल का उत्पादन जो 1980-81 मे 105 लाख मीट्रिक टन था और 1982-83 मे 210 6 लाख मीट्रिक टन हो गया था, अब 1983-84 मे बढ़कर उसके 260 लाख मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है। रेल द्वारा माल की ढुलाई को पिछले वर्ष से ऊचे स्तर पर बनाए रखने के लिए विशेष कोशिशे की गई है। बन्दरगाहो की क्षमता को बढाया जा रहा है और 1983-84 मे मुख्य बन्दरगाहो पर जो कुल यातायात होने की सम्भावना है, उम्मीद है कि वह दस सौ दस लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, यह अब तक का सबसे अधिक यातायात होगा।

5 औद्योगिक क्षेत्र मे विकास की गति जो वर्ष क पहले छह महीनो मे धीमी रही थी, उसमे वर्ष के आखिरी छह महीनो म सुधार हुआ है और 1983-84 मे कुल औद्योगिक विकास दर के 4.5 प्रतिशत हो जान की सम्भावना हे। औद्योगिक

निर्माण क्षेत्र में अच्छा उत्पादन रहा है। सूती कपड़ा, इंजीनियरी और सीमेंट उद्योगों मे भारी सुधार हुआ है।

6. देश के विभिन्न भागों में मुख्तलिफ दबावों के बावजूद वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्धो की स्थिति भी सन्तोषजनक बनी रही। आर्थिक विकास में गति को बनाए रखने के सरकार के अनुरोध का आम कामगारों पर अच्छा असर पड़ा है, जिसका पता उत्पादन मे हुई वृद्धि मे चल जाता है।

7. इस वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन की विकास दर लगभग 6 से 7 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है, जबकि 1982-83 में यह दर केवल 1.8 प्रतिशत थी। छठी योजना की पहले चार वर्षो मे कुल राष्ट्रीय उत्पादन की औसत विकास दर 5.4 प्रतिशत हो जाएगी। इस उपलब्धि पर देश जायज तौर पर गर्व कर सकता है।

8 कीमतो की स्थिति हमारे लिए चिन्ता का कारण रही है। 7 जनवरी, 1984 को मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 10 4 प्रतिशत तक पहुच गई है। अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के दबाव का अधिक कारण, सूखे की वजह से 1982-83 मे कृषि उत्पादन मे कमी, रहा था। इन दबावो का मुकाबला करने और मुद्रा के फैलाव को कम करने के लिए अनेक उपाए किए गए है, जिनमे खाद्यान्नो, तिलहनो और दालो का उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे विस्तार और उसे मजबूत बनाया जाना, अनाज की वसूली का जोरदार अभियान, आयात के जरिए समय पर घरेलू पूर्तियो का सीमान्त विस्तार, औद्योगिक उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहन और मुद्रा प्रणाली मे अधिक नकदी को घटाने के उद्देश्य से राजकोष और मुद्रा पर अंकुश लगाना शामिल है। 1983-84 की रिकार्ड फसल और बुनियादी ढाचे तथा औद्योगिक क्षेत्रों मे लगातार सुधार से आने वाले महीनो मे मुद्रा के फैलाव की दर को कम करने मे मदद मिलेगी। सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही उत्पादन और उसकी कुशलता तथा क्षमता के पूरे उपयोग की प्रेरणा को भी बनाए रखा है।

9. हमारे विदेशी भुगतान की स्थिति मे सुधार हुआ है। व्यापार-अन्तराल लगातार दूसरे वर्ष मे घट जाने की सम्भावना है। अप्रैल-अक्तूबर 1983 के दौरान (तेल को छोडकर) निर्यात मे 1982-83 की इसी अवधि की तुलना मे 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयातों का मूल्य (तेल निर्यात के अलावा) 2.5 प्रतिशत गिर गया। महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे उत्पादन की क्षमताओं के निर्माण और आयात की अधिक मात्रा को कम करने की नीति से लाभ हुआ है। एक दूसरी उत्साह-जनक बात यह है कि विदेशो मे रह रहे भारतीयो से धन की प्राप्ति मे काफी सुधार हुआ है।

10 चूकि हमारी सुरक्षित विदेशी मुद्रा मे वृद्धि हुई है, इसलिए सरकार ने स्वेच्छा से ही यह निर्णय किया है कि वह चालू वर्ष के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ एक्सटेंडेड फंड फेसेलिटी के अधीन कोई और अधिक धन नही लेगी। कुल 5 बिलियन एस० डी० आर० मे से हम केवल 3 9 बिलियन का ही उपयोग कर रहे है। इस प्रकार 1 1 बिलियन एस० डी० आर० का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरे विकासशील देशो की सहायता के लिए उपलब्ध हो गया है। हमारे देश के लोग विदेशी ताल-मेल की हमारी नीतियो की कामयाबी पर गर्व कर सकते है।

11. 20-सूत्री कार्यक्रम को, जिसमे निर्धनता को दूर करने के उपायो पर जोर दिया गया है, जोरदार ढग से लागू किए जाने से गाव के निर्धन लोगों की दशा मे सुधार हो रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 90 लाख ग्रामीण परिवारो को जिनमे अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन-जातियो के 32 लाख परिवार भी शामिल है, छठी योजना के पहले तीन वर्षों मे सहायता दी गई है। पहले तीन वर्षो के दौरान इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 2255 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। चालू वर्ष मे और भी 30 लाख परिवारो की सहायता की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन और अधिक रोजगार पैदा करने के लक्ष्यों को, योजना के पहले तीन वर्षों में पूरी तरह हासिल कर लिया गया और चालू वर्ष में भी इस दिशा मे प्रगति संतोषजनक है। 15 अगस्त, 1983 को एक नया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तालीम याफता बेरोजगारों को अपना रोजगार खुद चुनने के नए कार्यक्रम को भी भारी सफलता मिली है। 1983-84 के लिए 2.5 लाख शिक्षित व्यक्तियों की सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

12. माननीय संसद् सदस्यगण, 1983-84 में भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों से वाकिफ है। 17 अप्रैल 1983 को रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया गया था। इनसेट-1 बी को 30 अगस्त, 1983 को सफलता के साथ छोड़ा गया था, जो 15 अक्तूबर, 1983 से हमारे दूर-संचार, दूरदर्शन, रेडियो और मौसम विज्ञान कार्यक्रमों में सहायता दे रहा है। दूरदर्शन सेवाओं में भारी विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे कि इसकी सेवाओं के अन्तर्गत 1983-84 मे 23 प्रतिशत जनसख्या से बढ़कर 1984-85 तक 70 प्रतिशत जनसख्या आ सके। भारत ने दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और वह इस प्रकार इसका 15वां सलाहकार सदस्य राज्य बन गया है। अब तक दक्षिणी ध्रुव के तीन अभियान आयोजित किए गए हैं और वहां एक नियमित स्टेशन भी स्थापित किया जा चुका है। सबसे पहली बार दो महिला वैज्ञानिक उस महाद्वीप में गई है। हमने केन्द्रीय हिन्द महासागर में बहु धातु पिंड के व्यापक सर्वेक्षण हेतु एक मार्ग दर्शक क्षेत्र के लिए अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के पास रजिस्टर्ड करा लिया है। मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र की पहली इकाई, 2 जुलाई, 1983 को बनकर तैयार हो गई, इसका ढांचा और डिजाइन स्वदेश मे ही तैयार किया गया था। यह अब 200 मेगावाट तक बिजली तैयार कर रही है।

13. संसद् ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वास्थ्य की देख-रेख के निरोधात्मक, प्रेरक और पुनर्वास सम्बन्धी पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समाज को शामिल किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए दूर-दराज़ के देहाती इलाकों के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्धेपन पर नियंत्रण पाने के लिए भारी उपाए किए जा रहे है। परिवार नियोजन मे भारत की कोशिशों को उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल हुई, जब हमारी प्रधान मन्त्री को न्यूयार्क में 30 सितम्बर, 1983 को हुए एक विशेष समारोह मे संयुक्त राष्ट्र सघ का जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। गर्भधारण के प्रति 25.9 प्रतिशत दम्पत्तियों को सुरक्षित किया गया है और यह प्रतिशत अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परिवार नियोजन की मुख्तलिफ विधियों को अपनाने वालो की संख्या अप्रैल-दिसम्बर, 1983 मे पिछले वर्ष की इसी अवधि से 15 प्रतिशत बढ़ गई है।

14. शिक्षा मे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चो मे प्राथमिक शिक्षा को जिसमे लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, सब तक पहुंचाने और 1990 तक प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को खत्म करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहा रेडियो और टेलीविजन की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के एक जबरदस्त कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे हमारी यह कोशिश रही है कि विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नॉलोजी की संस्थाओं की कार्य प्रणाली मे सुधार किया जाए। शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए गठित दो आयोगों का कार्य प्रगति पर है।

15. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कला परिषद् की स्थापना की गई है, जो देश के सांस्कृतिक विकास और देश की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए मुख्तलिफ क्षेत्रों मे की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों मे सुधार लाने के लिए

नीतियां तैयार करेगी। हमारे पुस्तक उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की भी स्थापना की गई है।

16. देश एकता और अखण्डता के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए दृढ़ इरादे और सद्भावना के वातावरण में ही लगातार तरक्की कर सकता है। साम्प्रदायिक और पृथकतावादी तत्वों की विघटनकारी गतिविधियों, हिंसात्मक आन्दोलनों और अनेक क्षेत्रों में हुई राष्ट्र की उपलब्धियों को मिट्टी मे मिलाने की योजनाबद्ध कोशिशों से जो नुकसान पहुचा है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है। कुछ अन्दरूनी और बाहरी ताकतें भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को कमजोर करने के काम में लगी हुई है।

17. आज की जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक और राजनीतिक आजादी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सतर्कता पर ज्यादा ध्यान दें। हरएक देश-भक्त नागरिक को चाहिए कि वह ऐसी ताकतों को कुचलने मे सरकार के साथ सहयोग करे जो जाति, नस्ल, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों को बाटने की कोशिश करती है। हाल ही में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा के मत-भेद को भुलाकर एक मत से यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रीय एकता के ढांचे को मजबूत किया जाए और भारतीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। यह निर्णय बहुत ही उत्साह-जनक था। आन्दोलनों के समर्थन म हिंसा का सहारा लेने और धार्मिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों को शरण देने के विरुद्ध लगभग सभी पार्टियों में सहमति है। अपराधियों द्वारा पूजा स्थलों का इस्तेमाल किए जाने से धर्म के नाम पर धब्बा तो लगता ही है साथ ही उनकी पवित्रता भी नष्ट होती है और राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बढ़ते हुए इस अहसास को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मे तबदील करें जिससे कि देश में विभिन्न दलों और मुख्तलिफ वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय एकता के एक मजबूत सूत्र में बांधा जा सके।

18. आसाम में राज्य सरकार ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रयास किए हैं। इन कोशिशों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है, जिसने यह महसूस किया है कि हिंसा से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ी ही फैलती है। अधिकरणों ने विदेशियों के मसले पर एक संकल्प तैयार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अवैध रूप से देश में दाखिल होने वालों पर निगरानी रखने के लिए भी कड़े उपाय किए गए हैं। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य-गण समझौते और मेल-मिलाप की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

19. पंजाब में मासूम लोगों के खिलाफ दर्द-नाक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कुछ ताकतों ने सम्प्रदायों के बीच सदियो पुराने भाई-चारे के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिशें की हैं। परन्तु यह देखकर भारी सन्तोष होता है कि अधिकांश लोग चाहे वे किसीभी समुदाय के हों, नफरत के दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार से गुमराह नहीं हुए है। यह जरूरी है कि उस राज्य में फिर से शांति और सामान्य स्थिति कायम की जाए। सरकार हमेशा ही इस बात की फिक्र में रही है कि पंजाब की समस्याओं को सभी सम्ब-न्धित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए हल किया जाए।

20. हाल ही में, हरियाणा में साम्प्रदायिक हिंसा का फैलना एक दुखदायी घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभावित इलाकों में जल्दी ही फिर से शांति स्थापित हो जाएगी।

21. साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों में जो तेजी हुई है, वह सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय रही है। इनसे देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए खतरा है। एक ऐसे आतंकवादी गिरोह द्वारा जिसका यह दावा

है कि वह जम्मू व कश्मीर में पृथकतावादी आन्दोलन की नुमाइन्दगी करता है, ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक की कायरतापूर्ण हत्या किए जाने से हमारे लिए इस बात की जरूरत बढ़ गई है कि हम सतर्क और चौकस रहें। ऐसी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

22. हमारी राजनीतिक प्रणाली इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए काफी मजबूत और लचकदार है। हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थिति मजबूत है। भारत के लोगों ने बार-बार अपने इस दृढ़ निश्चय का सबूत दिया है कि हम बड़ी मुश्किलों से हासिल की गई अपनी आज़ादी और एकता की रक्षा कर सकते हैं। यह हमारा काम है कि हम उनकी इस असीम शक्ति और आदर्श का उपयोग राष्ट्र को मज़बूत बनाने के लिए करें।

23. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति शांतिजनक नहीं है। शस्त्रों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है और शस्त्रों पर सारे विश्व में 600 बिलियन डालर वार्षिक से ज्यादा खर्च हो रहा है। नि:शस्त्रीकरण की बातचीत मे कोई प्रगति नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इटरमीडियेट न्यूक्लीयर फोर्सेस को सीमित करने के सम्बन्ध में बातचीत स्थगित हो गई है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आशाएं भी इसी प्रकार से कमजोर पड़ गई हैं।

24. हमारे अपने क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण खराब हो गया है। हिन्द महासागर क्षेत्र का लगातार सैनिकीकरण होता जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में अति आधुनिक शस्त्रों के आ जाने से चिंता पैदा होती है। हम अपने दुर्लभ साधनों का इस्तेमाल विकास के कामो में करना पसंद करते है, परन्तु हम अपनी रक्षा जरूरतो के प्रति भी आंख बंद करके नही बैठ सकते। हमारे चारों ओर इस प्रकार की तैयारी के बावजूद, हमने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की अपनी नीति को कायम रखा है। हम चाहते है कि पाकिस्तान सरकार हमारे विरुद्ध किए जा रहे प्रचार को बंद करने के लिए दोस्ती, शांति और सहयोग के लिए हमारे प्रस्तावों और बेहतर संबंधों के लिए कदम उठाए और इस प्रकार की हमारी इच्छा का सकारात्मक रूप से उत्तर दे। श्रीलंका मे जातीय हिंसा से जिसमें भारतीय नागरिक और तमिल तथा भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति भारी सख्या में हताहत हुए थे और सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ था, सारे देश को स्वाभाविक रूप से गहरी चिन्ता हुई। यह सन्तोष की बात है कि श्री लंका सरकार ने हमारी सद्भावनापूर्ण कोशिशों के प्रस्ताव को मान लिया है, जिससे कि किसी व्यावहारिक राजनीतिक समझौते में सुविधा हो। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन से कोई मुस्तकिल और सन्तोषजनक हल निकल आएगा। चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने और सीमा प्रश्न के समझौते के उद्देश्य से कोशिशें की जा रही है। इस क्षेत्र के देशों के साथ अनेक बार यात्राओं का आदान-प्रदान और आपसी विचार-विमर्श हुआ है, जिससे कि प्रमुख समस्याओं का हल निकाला जा सके और आपसी सम्बन्धों में और सुधार लाया जा सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का सम्मिलित कार्य शुरू किया जाना इस दिशा में एक लाभदायक कदम था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हमें भूटान नरेश का स्वागत करने का अवसर मिला था।

25. नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन 1983 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस सम्मेलन ने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि गुट-निरपेक्ष नीति लगातार संगतिपूर्ण और उचित है। इस आन्दोलन की अध्यक्ष होने के नाते, प्रधानमंत्री ने शांति, नि शस्त्रीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में पहले से ही अनेक प्रारम्भिक कदम उठाये हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहल यह थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयार्क में अनौपचारिक रूप से शिखर स्तर पर विचार-विमर्श किए गए। इन विचार विमर्शों का भारी स्वागत हुआ है और इन्हें आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत को उपयोगी प्रक्रिया में सहायक माना है। फिलिस्तानी मुक्ति सगठन के भीतर हुई घट-

नाओं के सम्बन्ध में मंत्री स्तर पर गुट-निरपेक्ष देशों के दल का पश्चिम एशिया में भेजा जाना भी इस दिशा में एक कदम था। सरकार फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और दक्षिणी अफ्रीका तथा नामीबिया में मुक्ति आन्दोलनों को हर मुमकिन सहायता देने के लिए सैद्धान्तिक नीति के रूप में दृढ़ता से पाबद है। हमने नवम्बर में राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की थी। इससे औद्योगिक और विकासशील देशों के शासनाध्यक्षों को साथ-साथ मिलने का मौका मिला और शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पहल को नया समर्थन मिला।

26. सोवियत संघ और समाजवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की परम्परा बढ़ती जा रही है। हमें सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति, श्री यूरी आन्द्रोपोव के निधन पर गहरा दुःख हुआ है। प्रधानमंत्री सोवियत जनता के दुःख में भारत की हमदर्दी प्रकट करने के लिए मास्को गई थी। वहां सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के नए महासचिव श्री कान्स्टेटिन चर्ननको के साथ उनकी उपयोगी बैठक हुई थी, जिसमे आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाने की इच्छा को दोहराया गया।

27. प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में राष्ट्रपति रीगन के साथ उपयोगी विचार-विनिमय किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस मे "भारत उत्सव" मनाने की तैयारियां की जा रही है। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध दोनों ओर से की गई उच्च स्तर की अनेक यात्राओं से और भी मजबूत हुए थे।

28. मैंने चेकोस्लोवाकिया, क़तर और बहरीन की राजकीय यात्राएं की थी। प्रधानमंत्री ने युगोस्लाविया, फिन्लैड, डैन्मार्क, नार्वे, आस्ट्रिया, साईप्रस और ग्रीस की यात्राए की थी। वे पैरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिली थीं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के अवसर पर राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शामिल होने के अलावा, हमने अनेक प्रतिष्ठित विदेशी मेहमानों की भी मेज़बानी की थी। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष सम्मेलन के शुरू होने के अवसर पर भारत की राजकीय यात्रा की थी। बल्गारिया के राष्ट्रपति, जर्मनी संघीय गणराज्य के चान्सलर, मालदीवज़ गणराज्य के राष्ट्रपति और चकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हमारे देश में तशरीफ़ लाने वाले दूसरे विशिष्ट मेहमान थे। इन यात्राओं से भारत और इन देशों के बीच सहयोग और दोस्ती के सम्बन्धों को मजबूत बनाने में सहायता मिली है।

29. माननीय सदस्यगण, हमारा गणराज्य तनाव के दौर से गुज़र रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कामों के लिए देश के लोक सेवकों और जनता के नुमाइन्दों की दृढ़-निष्ठा की ज़रूरत है। जितना हम राष्ट्र से लेते हैं उससे ज्यादा हमें उसे देना चाहिए। आज हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति पुनः समर्पण की भावना की जरूरत है, ताकि हम सभी राष्ट्रीय एकता और विकास में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

30. मैं कामना करता हूं कि माननीय सदस्यों को अपने उन कठिन कार्यों में जो उनके सामने हैं सफलता हासिल हो।

जय हिन्द

Honourable Members,

It gives me pleasure to welcome you to this first session of Parliament in 1984 and to extend to you my best wishes for the successful completion of the budgetary and legislative business ahead.

2. In the current year the economy has made impressive recovery and progress overcoming the adverse effects of widespread failure of rains. Agricultural production is expected to grow by 9 per cent as against a decline of 4 per cent in the previous year. The production of foodgrains is likely to exceed the target of 142 million tonnes, compared to the actual production of 128.4 million tonnes in 1982-83 and the previous

best record of 133.3 million tonnes. The buoyancy in agricultural production reflects the soundness of the strategies and programmes followed over the years. The irrigation potential, which increased by 2.34 million hectares in 1982-83, is expected to increase further by 2.37 million hectares in 1983-84. Special efforts have been made to improve the utilisation of the potential so created. The high-yielding varieties programme has continued to expand and the 1983-84 coverage is expected to be 52 million hectares. Fertiliser consumption during 1983-84 will be well above the Plan target.

3. Special attention is being paid to dryland farming ; 4,.46 micro-watersheds have been identified for adoption of new technologies which will help the poorest rural communities A centrally sponsored scheme for assisting small and marginal farmers was also launched in 1983-84.

4. The recovery of the industrial economy and the improvement of the infrastructure have maintained good tempo. Coal production has shown steady improvement after September and the output during 1983-84 will be close to 140 million tonnes. During the first nine months of 1983-84, power generation has grown by about 5 per cent over the previous year. The production of crude oil, which was 10.5 million tonnes in 1980-81 and 21.0 million tonnes in 1982-83, is expected to increase further to 26 million tonnes in 1983-84. Special efforts have been made to maintain railway freight at a level higher than the previous year's. Port capacity is being expanded and the total traffic handled by the major ports in 1983-84 is expected to be an all-time-high of over 101 million tonnes.

5. The growth of the industrial sector, which was sluggish in the first half of the year, improved in the second half and an overall industrial growth rate of 4.5 per cent is likely in 1983-84. The manufacturing sector has performed well ; textiles, engineering and cement industries have shown substantial improvement.

6. The industrial relations situation also continued to be satisfactory during the year, in spite of the various stresses and strains in different parts of the country. The common worker has responded to the Government's call to maintain the momentum in economic development, which is reflected in increased production.

7. The growth rate of GNP this year is expected to be 6 to 7 per cent, as compared with only 1.8 per cent in 1982-83. In the first four years of the Sixth Plan, the average growth rate of GNP will be about 5.4 per cent. The country can take legitimate pride in this achievement.

8. The price situation has caused us anxiety. On January 7, 1984, the annual rate of inflation reached 10.4 per cent. The inflationary pressures on the economy largely reflect the low growth of output in 1982-83 due to the drought. A number of measures to counteract these pressures and to bring down inflation have been taken. They include : incentives for increasing production of foodgrains, oilseeds and pulses ; the expansion and strengthening of the public distribution system ; a vigorous procurement drive ; timely marginal augmentation of domestic supplies through imports ; incentives for increasing industrial production ; and enforcement of fiscal and monetary discipline aimed at the reduction of excess liquidity in the system. The record crop of 1983-84 and the continuing improvement in the infrastructure and the industrial sector will help in bringing down the rate of inflation in the months ahead. The Government have also taken several steps to curtail expenditure while maintaining the stimulus to production, efficiency and full utilisation of capacity.

9. The situation regarding our external payments has improved. The trade gap is expected to decline for the second successive year. During April-October 1983, exports (excluding oil) grew by 9.9 per cent compared to the same period of 1982-83, and the value of imports (net of oil exports) declined by 2.5 per cent. The policy of building production capacities in critical sectors and reducing bulk imports has yielded dividends. Another encouraging factor is the substantial improvement in the flow of funds from Indians abroad.

10. As our foreign exchange reserves have increased, the Government have

decided voluntarily not to make any further drawals under the Extended Fund Facility with the International Monetary Fund after the current year. Out of the total SDR 5 billion we are utilising only 3.9 billion, thus making SDR 1.1 billion available to the IMF to assist other developing countries. Our people can be proud of the success of our external adjustment policies.

11. Vigorous implementation of the Twenty-Point Programme, with its emphasis on anti-poverty measures, is transforming the condition of the rural poor. Under the Integrated Rural Development Programme, 9 million rural families, including 3.2 million families belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have been assisted in the first three years of the Sixth Plan. The total outlay on this programme during the first three years has been Rs. 22,530 million. In the current year another 3 million families are being helped. Targets to generate additional employment under the National Rural Employment Programme were fully achieved during the first three years of the Plan and the progress during the current year is satisfactory. A new Rural Landless Employment Guarantee Programme was launched on August 15, 1983. Rs. 6000 million have been allocated for it. There has been excellent response also to the new programme of providing self employment to the educated unemployed. A target of assisting 2.5 lakh educated persons has been set for 1983-84.

12. Honourable Members of Parliament are aware of the achievements of Indian science in 1983-84. On April 17, 1983, the Rohini satellite was placed in a near earth orbit. INSAT-1B was successfully launched on August 30, 1983. Since October 15, 1983 it has been serving our telecommunication, television, radio and meteorology programmes. A large expansion of television services has been planned to increase the coverage of population from 23 per cent in 1983-84 to 70 per cent by 1984-85. India has signed the Antarctic Treaty and has become the fifteenth consultative member state. So far three expeditions to Antarctica have been organised and a regular station established. For the first time two women scientists have gone to that continent. We have registered ourselves with the International Sea-bed Authority for a pioneer area for extensive survey of polymetallic nodules in the central Indian Ocean. The first unit of the Madras Atomic Power Station, which was designed and fabricated indigenously, attained criticality on July 2, 1983, and has been operating at power levels up to 200 MW.

13. Parliament has recently approved the National Health Policy which lays stress on preventive, promotive and rehabilitative aspects of health care. The core of the policy lies in community participation and the provision of health services through primary health centres to millions of families in the far-flung rural areas. Vigorous measures are being pursued for control of tuberculosis, leprosy and blindness. India's efforts in family planning received international recognition when our Prime Minister was given the United Nations Population Award at a special ceremony held on September 30, 1983, in New York. An all-time-high rate of around 25.9% has been achieved in couple protection. The number of acceptors of various family planning methods has increased by 15% in April—December 1983 over the corresponding period of the previous year.

14. In education the focus of attention continued to be on universalising elementary education in the age group of 6—14, with emphasis on girls' education, and on eradicating adult illiteracy by 1990. Taking advantage of the growth of television and radio, a vigorous programme of non-formal education has been planned. In higher education, it has been our effort to improve the functioning of universities and institutions of higher technology. The work of the two commissions set up to study the role of teachers has made progress.

15. A National Council of Arts has been established under the chairmanship of the Prime Minister which will formulate policies to improve the national endeavour in various fields of cultural development and conservation of our heritage. A National Book Development Council has also been set up for the development of our book industry.

16. The country can achieve sustained

progress only in a climate of harmony and determination to resist any threats to its unity and integrity. We can ill afford to ignore the harm done by disruptive activities of communal and secessionist elements, violent agitations and systemic efforts to denigrate the many-sided achievements of our people. Together, these trends in our body politic are weakening national cohesion. Some internal as well as external forces are at work to undermine India's political and social stability

17. In today's complex international situation, it is essential to intensify our vigilance to preserve our economic and political independence. Every patriotic citizen must cooperate with the Government in putting down forces that seek to divide the people on the basis of caste, creed, region or language. At the recent meeting of the National Integration Council there was a heartening consensus, cutting across differences of political outlook and ideology, that the fabric of national unity must be strengthened and the sense of Indianness promoted. There is agreement amongst most parties against the use of violence in support of agitations and the harbouring of anti-social elements in religious places. The use of places of worship by criminals affects their sanctity and harms the interests of the nation, apart from bringing a bad name to religion. I urge Honourable Members to convert this growing feeling into a national programme to bind different parties in the country and different sections of our people into a strong and vibrant national entity.

18. In Assam, the State Government have made strenuous efforts to promote peace and stability. This endeavour has been widely supported by the public who have realised that violence leads only to social and economic dislocation on a large scale. Tribunals have started working to facilitate a resolution of the foreigners' issue. Firm measures have also been taken to check illegal immigration. I trust Honourable Members will help in the process of reconciliation.

19. Punjab has witnessed tragic violence against innocent persons. Some forces have sought to weaken the centuries-old fraternal bonds between communities. It is however heart-warming that the majority of the people, irrespective of the community to which they belong have refused to be misled by the sinister propaganda of hate let loose. It is imperative to restore normalcy and peace in that State. The Government have always been anxious that the problems in Punjab be solved through dialogue between all concerned.

20. A distressing development is the recent spread of communal violence to Haryana. I hope that peace will soon be restored in the affected areas.

21. The Government have been seriously concerned over the acceleration of the activities of communal and anti-national elements which constitute a serious threat to the security and integrity of the country. The dastardly assassination of an Indian diplomat in the United Kingdom by a gang of terrorists who claim to represent a secessionist movement in Jammu and Kashmir has emphasised the need for vigilance and preparedness on our part. The wider repercussions of such developments should be kept in mind.

22. Our polity has sufficient strength and resilience to overcome these difficulties. The health of our democratic institutions is sound. The Indian people have time and again shown their determination to protect their hard-won freedom and unity. It is up to us to harness their unbounded energy and idealism for the strengthening of the nation.

23. The international situation is disturbing. The arms race has continued unabated with the global expenditure on armaments exceeding $ 600 billion annually. Disarmament negotiations have not registered any progress. The talks between the USA and the Soviet Union on the limitation of the Intermediate Nuclear Forces have been suspended. The prospect of redressing economic disparities is equally bleak.

24. The security environment in our own region has worsened. The militarisation of the Indian Ocean area continues. The induction of highly sophisticated weapons in our neighbourhood causes concern. We prefer to spend our scarce

resources on development, but we cannot afford to be blind to our defence requirements. In spite of this build-up all around us, we have persevered in our policy of seeking friendship with all our neighbours. We should like the Government of Pakistan to respond positively to our desire for better relations and our proposals for friendship, peace and cooperation and to take steps to curb the propaganda directed against us. The ethnic violence in Sri Lanka, in which Indian nationals and Tamils and others of Indian origin suffered heavy casualties and loss of property, naturally caused deep concern to the entire country. It is gratifying that the Sri Lanka Government accepted our offer of good offices to facilitate a viable political settlement. We hope that the All-Parties Conference will lead to a lasting and satisfactory solution. Efforts aimed at the normalisation of relations with China, including the settlement of the boundary question are continuing. A number of visits have been exchanged and discussions held with the countries of the region with a view to resolving outstanding problems and further improving bilateral relations. A positive development was the launching of an integrated programme of South Asian Regional Cooperation. We were privileged to have the King of Bhutan as our chief guest on Republic Day this year.

25. An event of high significance in 1983 was the Seventh Conference of Non-Aligned Countries in New Delhi. The Conference reaffirmed the continued relevance and validity of the policy of non-alignment. The Prime Minister, as Chairperson of the Movement, has already taken a number of initiatives to promote peace, disarmament and economic cooperation. The most significant initiative was the organisation of informal consultations at summit level in New York at the time of the UN General Assembly. These consultations were widely acclaimed as having contributed to a useful process of dialogue on some of the critical issues of the day. Another step was the sending of a non-aligned ministerial group to West Asia in connection with the developments within the Palestinian Liberation Organisation. The Government firmly adhere to the principled policy of extending every possible support to the PLO and to liberation movements in Southern Africa and Namibia. We also played host to the Commonwealth Heads of Government Meeting in November. It brought together Heads of Government belonging to industrialised as well as developing countries and gave new support to initiatives for peace and international cooperation.

26. The tradition of friendly cooperation with the Soviet Union and the Socialist countries is growing. We were deeply grieved at the passing away of Mr. Yuri Andropov, the General Secretary of the CPSU and President of the USSR. The Prime Minister flew to Moscow to convey India's sympathy to the Soviet people in their sorrow. She had a useful meeting with Mr. Konstantin Chernenko, the new General Secretary of the CPSU, at which the desire to strengthen mutual relations was reiterated.

27. The Prime Minister had a useful exchange of views with President Reagan in New York. Preparations are under way for the holding of Festivals of India in the United States and France. Our relations with the countries of Western Europe were further strengthened by various high-level visits in both directions.

28. I paid State visits to Czechoslovakia, Qatar and Bahrain. The Prime Minister visited Yugoslavia, Finland, Denmark, Norway, Austria, Cyprus and Greece. She also met the President of France in Paris. In addition to the participation of Heads of State/Government at the NAM Summit and CHOGM, we also had the privilege of playing host to a number of distinguished visitors from abroad. Queen Elizabeth II combined a State visit to India with the opening of the CHOGM. The President of Bulgaria, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, the President of the Republic of Maldives and the Prime Minister of Czechoslovakia were other distinguished guests. These visits have helped to strengthen the friendly ties and cooperation between India and these countries.

29. Honourable Members, the Republic is passing through a period of stress.

Important national tasks require steadfast devotion on the part of its public servants and people's representatives. We must give more to the nation than we take from it. A rededication to national ideals is needed so that all of us may give of our best to the cause of national unity and progress.

30. I wish the Honourable Members all success in their strenuous endeavours that lie ahead.

Jai Hind

12.42 hrs.

OBITUARY REFERENCES

MR. SPEAKER : Hon. Members, as we meet today after an interval of two months, it is my sad duty to inform the House of the passing away of Mr. Yuri Vladimirovich Andropov, General Secretary of the Central Committee of the Soviet Communist Party and Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR, Sarvashri J.C. Barve, C.M. Stephen and Dr. B.N. Singh, sitting Members and four former Members, namely, Sarvashri Achal Singh, P. Sivasankaran, Baijnath Kureel and Y. Shaiza.

Mr. Yuri Vladimirovich Andropov, General Secretary of the Central Committee of the Soviet Communist Party and Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR, passed away on 9th February, 1984 at the age of 69 years.

Born in June, 1914 in the family of a railwayman, President Andropov started his career as a telegraph operator. He soon embarked on a career as a Communist Party functionary and rapidly rose in the party ranks. During the Second World War he actively participated in the war. He was named as 'Army General' in 1976. Besides being General Secretary of the Central Committee of Soviet Communist Party, he was elected as the Head of the State in 198 and had the distinction of simultaneously holding two top posts of his country during the brief period of his leadership of the country.

Recipient of several of the highest awards, he was four times winner of the Order of Lenin and was conferred the coveted title of 'Hero of Socialist Labour.'

An outstanding statesman, he dedicated his life for the ideals of world peace and containment of the nuclear arms race.

At home he made relentless efforts to enforce strict labour discipline and pragmatically endeavoured to give workers greater say in management.

A staunch friend of India, he made the strengthening of bonds with India a keystone of his foreign policy and took keen personal interest in promoting increasing Indo-Soviet co-operation in the fields of trade and economic relations.

We pay our tributes to the memory of this great statesman of our time. In his death the Soviet Union has lost a staunch patriot and India a true friend and supporter.

Shri J.C. Barve was a sitting Member of the House representing Ramtek constituency of Maharashtra.

Earlier he had been a member of Sixth Lok Sabha during 1977-79 and a Member of Maharashtra Legislative Council during 1972-77.

A veteran freedom fighter, Shri Barve took active part in the 'Quit India' Movement in 1942 and suffered imprisonment for several years.

An agriculturist, Shri Barve took keen interest in the dovelopment of irrigation, agriculture and fisheries. He was associated with several co-operatives and other social institutions in various capacities. He also took keen interest in welfare measures for uplift of fishermen.

Shri Barve passed away on 16th January, 1984 at Nagpur at the age of 63 years.

Shri C.M. Stephen was a sitting Member representing Gulbarga constituency of Karnataka State. Earlier, he had been a Member of Fifth and Sixth Lok Sabha elected from Kerala State during 1971-79 and a Member of Kerala Legislative Assembly dur-